ख़बर का असर: श्रीराम अस्पताल ने फोन नंबर बदला

फ़रीदाबाद (ममो) तिकोना पार्क में सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से क़ब्ज़ा करने वालों ने आखिरकार श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल का फ़ोन नंबर बदल ही दिया। मज़दूर मोर्चा के पाठकों को याद होगा कि किस तरह क़ब्ज़ा करने वाले गैंग ने सुकृत सेवा मंडल के नाम से पर्चियाँ काटकर कमाई कर रहे थे। इस पर्ची पर और अस्पताल के बोर्ड पर एक ही नंबर था। मज़दूर मोर्चा की खबर छपने के बाद अवैध क़ब्ज़ाधारियों ने बोर्ड पर वो नंबर हटाकर अब नया नंबर लिख दिया है। हम नए और पुराने दोनों बोर्ड का फ़ोटो छाप रहे हैं। इस बीच जिला रजिस्ट्रार फ़रीदाबाद द्वारा बैठाए गए प्रशासक का कहीं कोई अता-पता नहीं है। 8 जून को उसका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है जो आगे बढ़ा नहीं है। प्रशासक की आड़ में अस्पताल पर क़ब्ज़ा करके बैठे लोग अभी भी रोज़ाना अस्पताल आ रहे हैं। प्रशासक ने अवैध क़ब्ज़ाधारियों में से कुछ लोगों को कोविड सेंटर चलाने वाली कमेटी में भी लिया था। प्रशासक के ग़ायब होने पर अब इस कमेटी के औचित्य पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। पंजाबी बिरादरी में इस मामले पर भाजपा नेताओं द्वारा निभाई गई विवादास्पद भूमिका की थू-थू हो रही है।

यही मौका है

-नबारुण भट्टाचार्य
(अनुवाद - लाल्टू)

यही मौका है, हवा का रुख है
ग़रीबों को भगाने का
मज़ा आ गया, भगाओ ग़रीबों को
कनस्तर पीट कर जानवरों को भगाते हैं जैसे
हवा चल पड़ी है
ग़रीब अब सही फँसे हैं
राक्षस की फूँक से उनकी झोपड़ी उड़ जा रही है
पैरों तले सरकती ज़मीन
और तेज़ी से गायब हो रही है
मज़ा ले-लेकर यह मंज़र भोगने का
यही वक्त तय है
इतिहास का सीरियल चल रहा है
वक्त पैसा है और यही वक्त है
ग़रीबों को लूट मारने का

ग़रीब अब गहरे जाल में फँस गए हैं
वे नहीं जानते कि उनके साथ लेनिन है या लोकनाथ
वे नहीं जानते कि गोली चलेगी या नहीं!
वे नहीं जानते कि गाँव-शहर में कोई उन्हें नहीं चाहता
इतना न-जानना बुखार का चढ़ना है
जब इंसान तो क्या, घर-बार, बर्तन-बाटी
सब तितली बन उड़ जाते हैं
यही ग़रीब भगाने का वक्त कहलाता है
कवियों ने ग़रीबों का साथ छोड़ दिया है
उन पर कोई कविता नहीं लिख रहा
उनकी शक्ल देखने पर पैर जल जाते हैं
हवा चल पड़ी है, यही मौका है
ग़रीबों को भगाने का
कनस्तर पीट कर जानवरों को भगाते जैसे
मौका है ग़रीबों को भगाने का
यही मौका है, हवा चल पड़ी है।

स्वाद / विजेंदर मसिजीवी

- पहली बात- स्वाद ऐसी निजी चीज नहीं है जैसी आप माने बैठे हैं, इसकी बाकायदा सामाजिक निर्मिति है- आपकी जाति, धर्म, वर्ग, लैंगिकता... आपका सामाजिक इतिहास भी, ये सब मिलकर आपके स्वाद का निर्माण करते हैं जैसे अन्य रुचियों, अरुचियों का।

- स्वाद का भी अपना सत्ता चरित्र होता है, जिसके पास परिवार/समाज/राष्ट्र में सत्ता होती है उस वर्ग/व्यक्ति के स्वाद को प्रमुखता मिलती है।

- क के स्वाद के लिए ख के व्यवहार को नियंत्रित करने की जुगत में जो चतुराई है वही असल बेईमानी है। स्वाद शुकुल पुरुष का है लेकिन उसके लिए शुकुल/गैर शुकुल स्त्रियों का व्यवहार तय किया जाएगा- ये नंगी बेईमानी है, जिसे न देख पाने के लिए आला दर्जे की बेशर्मी चाहिए।

- असली बेईमानी लेकिन स्वाद से ज्यादा उसे कॉंटेक्चुअलाइज करने में निहित होती है- स्मृति, नोस्टाल्जिया में। ये बताने की तो जरूरत नहीं कि याद एक शातिर जुगत है, हमें क्या और कैसे याद रहता है इसमें ढेर पूर्वग्रह और सामाजिक समीकरण काम करते हैं तो हमारा नोस्टाल्जिया और स्मृति हमारे पूर्वाग्रहों, सत्ताई सामाजिक स्थिति की ही देन है। किसी नामधारी की पत्नी जो किसी और नामधारी की बेटी है फिर भी बेनाम रह जाती है, के हाथों की चटनी की गंध और स्वाद से जो नोस्टाल्जिया ट्रिगर हुआ ये वैसा अनायास नहीं है जैसा आपको लगता है। इसमें आपकी लिंग, धर्म, जाति, राष्ट्रीयता ने वैसे ही भूमिका अदा की है जैसे किसी भी सामाजिक उत्पाद के मामले में होता है।

कुल मिलाकर घाघपन को मोहक सी चटनीचाह समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, डेविल डिटेल्स में ही रहता है।

व्यंग्य: मुल्लों को टाइट करने का बढ़िया इंतजाम

यूसुफ किरमानी

जनसंख्या नियंत्रण के लिए असम और यूपी सरकार की दो बच्चों की नीति को हमारा पूरा समर्थन है।

यहां हमारा से मतलब मेरा नहीं पढ़ें। हमारा से मतलब समस्त मुसलमान, जिनकी ठेकेदारी मेरे पास है, उनकी ओर से मैं इस नीति का समर्थन देने का वचन देता हूं।

यह बहुत अच्छी नीति है, जितनी जल्दी हो सके इसे लागू किया जाना चाहिए।

इस नीति से तो मुल्ले एकदम टाइट होकर जमीन पर आ गिरेंगे। मुसलमानों की चूड़ी कसने के लिए दो बच्चों की नीति से अच्छा कदम और नहीं हो सकता। वैसे मुल्ले चाहें तो आपदा में अवसर समझकर इस योजना को लपककर आत्मसात कर लें और भारत की मुख्यधारा में न रहने का अपना कथित दाग धो लें।

हालांकि सरकार को यह नीति सिर्फ मुल्लों के लिए लाना चाहिए क्योंकि जल्द ही गैर मुसलमानों के कई समुदाय और राज्य इसका विरोध करेंगे। ऐसे में सरकार को दिक्कत आ सकती है। अभी भी समय है, दो बच्चों की पॉलिसी सिर्फ मुसलमानों के लिए बने।

...जो तथाकथित बुद्धिजीवी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 7 भाई-बहन, प्रधानसेवक मोदी के 6 भाई-बहन, अमित शाह 7 बहन-भाई, मायावती के 8 भाई-बहन, लालू यादव के 12 बच्चों का उदाहरण दे रहे हैं, वे देशद्रोही हैं। अरे भाई, पुरानी बातों पर मिट्टी डालें।...पुराने जमाने की आनंद फिल्म का आनंद कुछ और था, मौजूदा दौर का आनंद कुछ और है।

हालांकि, हमारे पड़ोसी पंजाबी परिवार के तीन बच्चे, उससे आगे एक और पंजाबी परिवार के पांच बच्चे, उससे भी आगे शर्मा परिवार के चार बच्चों वाले पिता आज दबी जबान से पार्क में इस नीति का विरोध करते नजर आए लेकिन खुलकर कुछ कह नहीं सके।

उनका कहना था कि हमारे तीन-तीन, चार-चार बच्चे तो फिर भी ठीक हैं लेकिन जनसंख्या बढ़ाने में असली योगदान मुल्लों का है। इसलिए यह नीति तो ठीक है लेकिन इससे हम हिन्दुओं को छूट मिलनी चाहिए। ये दो बच्चों वाला कानून सिर्फ मुल्लों के लिए हो।

हो सकता है अखिलेश यादव जैसे इसका विरोध करें, क्योंकि अगर मुल्लों ने इस नीति को समर्थन दे दिया (हालांकि यह तय है कि समर्थन मिलेगा) तो वो बेचारा किस मुद्दे को आधार बनाकर चुनाव लड़ेगा। उसे डर होगा कि मुल्ले इस योजना की आड़ में भाजपा से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जो दो-चार फीसदी यादव उसके पास बचे हैं, उनसे भला सत्ता में कैसे वापसी की जा सकेगी।

इस नीति का विरोध अविवाहित राहुल गांधी भी कर सकता है क्योंकि उसे अभी विवाह की कठिन परीक्षा से गुजरना है। वह अभी से फैमिली प्लानिंग कैसे बता दे। उसके खानदान में मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी तक बस एक या दो बच्चे पैदा करने का ही सिलसिला रहा है। यानी मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद के परदादा जब बच्चों की फौज खड़ी कर रहे थे तो नेहरू खानदान एक या दो बच्चों से काम चला रहा था।

बहरहाल, प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून में कुछ प्रावधान और भी किए जा सकते हैं...

देश की खातिर जिस तरह मोदी, योगी, मोहन भागवत, मायावती ने विवाह नहीं किया, देश में ऐसे लाखों युवक होंगे जो रोजगार के अभाव में अविवाहित हैं या जिन्होंने आगे विवाह नहीं करने का फैसला लिया है, उन्हें सरकार फ्लैट, गाड़ी वगैरह देकर सम्मानित करे। सरकार के ऐसा करने पर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ सकती है और जनसंख्या पर नियंत्रण और प्रभावी तरीके से लागू हो जाएगा। इसमें पकौड़ा तलने वाले युवकों को सिर्फ फ्लैट या कार में से कोई एक चीज देकर उनका सम्मान सीमित किया जा सकता है क्योंकि पकौड़े तल कर वे पैसा तो कमा ही रहे हैं।

तमाम राजनीतिक दल भी चाहें तो मतदाताओं का दिल जीतने के लिए तमाम घोषणाएं कर सकते हैं। जैसे अविवाहित रहने वाले युवक-युवतियों को टिकट देकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। एलजीबीटी समुदाय को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण में उनसे बड़ा योगदान तो कोई दे ही नहीं सकता। इसी तरह गोदी मीडिया से हाल ही में बेरोजगार किए गए दो-तीन बच्चों वाले पत्रकारों के लिए भी कोई योजना लाई जा सकती है। गोदी मीडिया में मौजूद पत्रकारों की गिनती कराकर उनके बच्चों की सूची प्रकाशित की जानी चाहिए।

लेखकों, कवियों को भी इस योजना के दायरे में लाया जा सकता है। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार सिर्फ उसी लेखक को मिले अविवाहित हो। अगर वो मंदिर आदि के लिए चंदा देकर अपनी आस्था प्रकट कर चुका हो तो उस लेखक को साहित्य पुलित्जर देने की घोषणा की जा सकती है। इस संबंध में जनता से भी सुझाव आमंत्रित हैं। अच्छे सुझाव वालों को मैं सरकार से बात करके पुरस्कार आदि की व्यवस्था करा सकता हूं।